



मध्यप्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा में मजदूरों को सबसे कम दिहाड़ी, केरल में सबसे ज्यादा मिल रही मजदूरी

रिजर्व बैंक के अनुसार कृषि, निर्माण, बागवानी और गैर-कृषि क्षेत्रों में मजदूरी कर रहे श्रमिकों की दिहाड़ी राष्ट्रीय औसत से भी कम

हलधर किसान 1 (98262 25025) देश में जिस गुजरात को विकास का मॉडल माना जाता है, उसी गुजरात में मजदूरों की दिहाड़ी सबसे कम है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में खेतीहर मजदूरों की दिहाड़ी का राष्ट्रीय औसत 323.2 रुपये था। गुजरात में ये 220.3 रुपये था जबकि केरल में ग्रामीण खेतीहर मजदूरों को 726.8 रुपये की दिहाड़ी मिली है। अध्ययन किए गए 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 50 फीसदी में मजदूरों को राष्ट्रीय औसत से ज्यादा देहाड़ी मिल रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 19 नवंबर, 2022 को जारी रिपोर्ट 'हेडलुक ऑफस्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स' से पता चला है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और त्रिपुरा में बढ़ती महंगाई के बीच 2021-22 में सबसे कम दिहाड़ी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ दूध, फल, सब्जियों और अन्य जरूरी सामान की कीमतों आसमान छू रही हैं।

रिजर्व बैंक के अनुसार इन राज्यों में कृषि, निर्माण, बागवानी और गैर-कृषि क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में मजदूरी कर रहे श्रमिकों की दिहाड़ी राष्ट्रीय औसत से भी कम है। पता चला है कि जहां खेती में काम कर रहे पुरुष मजदूरों को 217.8 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी मिल रही है। वहीं गुजरात में यह मजदूरी 220.3 रुपये प्रति दिन है। इन राज्यों के बाद ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार का नंबर आता है।

वहीं दूसरी तरफ केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों में लगे मजदूरों को देश में सबसे ज्यादा 726.8 रुपये की दिहाड़ी मिल रही है। इसके बाद जम्मू-कश्मीर में 524.6 रुपये, हिमाचल प्रदेश 457.6 रुपये और तमिलनाडु में मजदूरों

को हर दिन के हिसाब से 445.6 रुपये मिलते हैं।

रिपोर्ट से पता चला है कि देश में हर दिन कृषि क्षेत्र में लगे मजदूरों को औसतन 323.32 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते हैं। वहीं अध्ययन किए गए 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 50 फीसदी में श्रमिकों को राष्ट्रीय औसत से ज्यादा मजदूरी मिलती है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु शामिल हैं। वहीं यदि कस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की बात करें तो वहां भी स्थिति कृषि क्षेत्र जैसी ही है। जहां त्रिपुरा में प्रति मजदूर औसतन 250 रुपये दिहाड़ी है वहीं मध्य प्रदेश में यह 266.7 रुपये और गुजरात में 295.9 रुपये दर्ज की गई है। वहीं यदि केरल की बात करें तो वहां ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण क्षेत्र में लगे मजदूर को हर दिन औसतन 837.7 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर (519.8 रुपये) और तमिलनाडु (478.6) में भी इस क्षेत्र के मजदूरों की देहाड़ी 450 रुपये से ज्यादा है।



महंगाई के मुताबिक काफी कम है मजदूरी

देखा जाए तो आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण मजदूरी में हुई वृद्धि बढ़ती महंगाई के साथ तालमेल बेटाने में विफल रही है। इस बीच जहां खुदरा महंगाई दर 6.77 फीसदी दर्ज की गई। हालांकि देखा जाए तो अक्टूबर में यह सात फीसदी से नीचे गिर गई थी। फिर भी इसके बावजूद यह आरबीआई के दो से छह फीसदी की सहनशीलता सीमा से काफी ऊपर है। इस बीच सरकार द्वारा गेहूं और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद अक्टूबर 2022 में अनाज और उत्पादों की कीमतों में वृद्धि जारी रही।

अक्टूबर 2022 में अनाज की महंगाई नौ साल के उच्चतम स्तर 12.08 फीसदी पर पहुंच गई, जो सितंबर 2022 में 11.53 फीसदी से भी ऊपर थी। आरबीआई के आंकड़ों में यह भी सामने आया है कि गैर-कृषि क्षेत्र से जुड़े मजदूरों को भी केरल, जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मजदूरी मिल रही है। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात और त्रिपुरा में उनकी देहाड़ी सबसे कम है। हालांकि देखा जाए तो 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान गुजरात में मजदूरी दर में मामूली वृद्धि हुई है। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में इसमें गिरावट दर्ज की गई है, जबकि त्रिपुरा में भी ऐसा ही हाल है।

मजदूरों को कितनी दिहाड़ी मिलती है?

■ 2020-21 ■ 2021-22



आधार लिंक

करने पर

1.86 करोड़

किसान हुए

आपत्र,

पीएम

किसान

सामान निधि

के लाभ से

नहीं होंगे

वर्चित

हलधर किसान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपये की अधिक मद्दद दी जाती है। लेकिन, सरकार ने 12वीं किस्त जारी करने से पहले सूची में करीब 1.86 करोड़ किसानों के नाम काट दिये गए हैं। अब तक इस योजना का लाभ 10.45 करोड़ से अधिक किसानों को मिला है जो 12वीं किस्त में घटकर 8958 करोड़ रह जाएगा। यह सूची किसानों के डेटा को क्लीन करने के लिए आधार लिंक करने वाला चौथा डिजिटल फिक्स्टर आजमाने के दौरान सामने आई है। मिली जानकारी अनुसार उत्तर प्रदेश में इस चौथे फिक्स्टर के चलते 58 लाख किसान कम हो गए जबकि पंजाब में यह संख्या 17 लाख से घटकर 2 लाख रह गई। 15 राज्य ऐसे हैं जहां यह संख्या 10.15 लाख घटी है, जबकि इतने ही राज्यों में लाभार्थी बढ़े हैं। दरअसल, कृषि मंत्रालय ने किसानों के डेटा को पारदर्शी बनाने के लिए तीन फिक्स्टर पहले से लगाए थे। फिर आधार लिंकड पेमेंट के रूप में चौथा फिक्स्टर लगाया तो लाभार्थियों की संख्या घटते गई।

योजना में पारदर्शिता और अपात्रों की पहचान करने के लिए किसानों का ई-केवाईसी लागू कर दिया है और आधार पेमेंट ब्रिज के जरिए भुगतान किया जा रहा है। किसानों की संख्या कम होते देख केंद्र ने राज्यों के साथ मिलकर गांव-गांव में टीम भेजने को कहा है। ताकि अस्थायी हकदार स्कीम से बाहर न हों।

25 नवंबर तक 358.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई हुई

रबी सीजन में फसल उत्पादन बेहतर रहने की उम्मीद, रकबा 24 लाख हेक्टेयर बढ़ा: केंद्रिय कृषि मंत्री तोमर

हलधर किसान।
(98262 25025)

दिल्ली। इस वर्ष 25 नवंबर तक 358.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई हुई है जो पिछले वर्ष के 334.46 लाख हेक्टेयर की तुलना में 24.13 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। केंद्रिय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई कि मिट्टी में नमी की स्थिति की अनुकूलता, बेहतर सिंचाई और उर्वरकों की उपलब्धता से आने वाले दिनों में रबी फसल क्षेत्र कवरेज में और तेजी आएगी।

केंद्रिय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि बुवाई क्षेत्रफल में वृद्धि और मिट्टी में नमी की स्थिति अनुकूल होने के कारण सरकार को मौजूदा रबी सीजन में बोई जाने वाली फसलों के बेहतर उत्पादन की उम्मीद है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कृषि मंत्री ने रबी फसलों की स्थिति का जायजा लेने के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि रबी की बुवाई का रकबा एक साल पहले की तुलना में अब तक 24.13 लाख हेक्टेयर अधिक है। बयान में कहा गया कि इस साल अभी तक 152.88 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई हुई है जो पिछले वर्ष के 138.35 लाख हेक्टेयर

की तुलना में 14.53 लाख हेक्टेयर अधिक है। इस साल गेहूं की बुवाई ने पिछले चार साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।

गेहूं बुवाई में एमपी आगे

ताजा आंकड़ों के अनुसार, गेहूं की सबसे ज्यादा बुवाई मध्य प्रदेश (6.40 लाख हेक्टेयर) में हुई है। इसके बाद राजस्थान 5.67 लाख हेक्टेयर, पंजाब 1.55 लाख हेक्टेयर, बिहार 1.05 लाख हेक्टेयर, गुजरात 0.78 लाख हेक्टेयर, जम्मू और कश्मीर 0.74 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश 0.70 लाख हेक्टेयर हैं।

इस रबी सत्र में 25 नवंबर तक तिलहन खेती का रकबा 13.58 प्रतिशत बढ़कर 75.77 लाख हेक्टेयर हो गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह रकबा 66.71 लाख हेक्टेयर था। इसमें से पहले के 61.96 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 70.89 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुवाई हो चुकी है।

दालों के मामले में, उक अवधि में पहले के 94.37 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस बार थोड़ा कम यानी 94.26 लाख हेक्टेयर दलहन फसल बोई गई है। मोटे अनाज की बुवाई 26.54 लाख हेक्टेयर में की गई, जो रकबा पहले 26.70 लाख हेक्टेयर था। जबकि चावल की बुवाई 9.14 लाख हेक्टेयर में हुई, जो पहले 8.33 लाख हेक्टेयर था।

फसल वर्ष 2021.22 जुलाई-जून में भारत का खाद्यान्न चावल, गेहूं, दाल और मोटे अनाज का उत्पादन 31 करोड़ 57.2 लाख टन रहा। इसमें से लगभग 16 करोड़ टन का उत्पादन रबी सत्र में हुआ।



मप्र में 42.20 लाख हेक्टेयर में गेहूं और 14.71 लाख हेक्टेयर में चने की हुई बुआई

मप्र कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 124 लाख 77 हजार हेक्टेयर है। इस वर्ष 139.06 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें ली जाएंगी। कृषि विभाग के अनुसार अब तक 77.60 लाख हेक्टेयर में बुआई कर ली गई है। इसमें राज्य की प्रमुख रबी फसल गेहूं की बोनी 42.20 लाख हेक्टेयर में हुई है। जबकि गत वर्ष अब तक 38.50 लाख हे. में गेहूं बोया गया था। दूसरी प्रमुख फसल चने की बोनी अब तक 14.71 लाख हेक्टेयर में हो गई है जो गत वर्ष समान अवधि में 18.22 लाख हे. में हुई थी। अन्य फसलों में अब तक मटर 1.76 लाख हे. में, मसूर 4.98 लाख हे. में बोई गई है। राज्य की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों की बोनी 12.53 लाख हे. में हुई है जबकि इस वर्ष 13.07 लाख हे. लक्ष्य रखा गया है। वहीं गत वर्ष अब तक सरसों 9.44 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी। अलसी की बोनी 89 हजार हेक्टेयर में हुई है। इस वर्ष मात्रा 1.40 लाख हेक्टेयर में लिया जायेगा, अब तक इसकी बुवाई 26 हजार हेक्टेयर में हुई है जबकि गत वर्ष इस अवधि में 19 हजार हेक्टेयर में मात्रा बोया गया था। प्रदेश में अब तक कुल अनाज फसलें 42.47 लाख हे. में, दलहनी फसलें 21.45 लाख हे. में एवं तिलहनी फसलें 13.42 लाख हे. में बोई गई हैं।

क्या आप अपना खुद का व्यापार स्थापित करना चाहते हैं ?

मध्य भारत की तेजी से बढ़ती हुई रिटेल चैन आउटलेट बीज भंडार की फ्रेंचाइजी ले और बने अपनी दुकान के मालिक

बीज भंडार की फ्रेंचाइजी लेने के लिए संपर्क करें।

बीज भंडार, जैन एग्रो एजेंसी, खरगोन मोबा. 8305103633

बीज भण्डार™



उन्नत खेती के उत्तम बीज

किसान के लिए पूस की रात कभी खत्म नहीं होती

गाँधी जी ने कहा था कि 'भारत की आत्मा गांवों में बसती है' तो जरूर उनके ध्यान में किसानों की साइगी और संघर्ष रहा होगा। क्योंकि गांव का बड़ा हिस्सा किसान से ही मिलकर बनता है इसलिए किसान के बगैर गांव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक समय था कि किसान गांव का केंद्र बिन्दु था। अन्य तमाम जातियां आजीविका के लिए किसानों की मोहताज होती थी। इसके अलावा खेतिहर मजदूरों की आजीविका भी खेती .किसानी पर टिकी हुई थी। गाम अपने आप में एक आत्मनिर्भर इकाई था। जहां जरूरत की चीजें एक-दूसरे से पूर्ण कर ली जाती थी। हमारे विद्यालय, हमारी पुलिस और फौज, हमारी अदालतें सब किसानों की कमाई के बल पर ही चलती थी। सरकार और जमींदार उन्हीं से लगान वसूलकर अपनी जरूरतें पूरी करते थे।

पूस की रात किसान जीवन की त्रासदी का एक रूपक है। वह एक ऐसी त्रासदी है जो आज भी बदस्तूर जारी है। कहा जाता है कि भारतीय किसान कर्ज में ही पैदा होता है, कर्ज में ही जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। किसान अब फसल बर्बादी की बचाव नीलगाय से नहीं बल्कि लावारिस गाय और आबारा सांड से कर रहा है। बदलते परिवार में फर्क सिर्फ इतना ही हुआ है। आज भी वह पूस की रात में जगकर अपने फसलों की रखवाली कर रहा है।

संपादकीय...

फसल और उसकी जान की कीमत जानवर के आगे नगण्य है। सरकारें कोई भी हो वह जीतती किसानों के वोट से हैं लेकिन जीतने के बाद बड़े-बड़े पांच सितारा होटलों में उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को बुलाकर निवेश लाने का ढोल पीटते हैं। लेकिन उस निवेश का अंता. पता नहीं चलता है। काश इतना ही ध्यान किसानों के पानी, बिजली, डीजल, बीज, मंडी और उचित दाम पर उनकी फसल की खरीददारी सुनिश्चित किया जाता तो भारत के आधे से ज्यादा किसान ऐसे ही खुशहाल रहता। फिर न किसान को कर्ज लेना पड़ता, न आत्महत्या करना पड़ता और न ही चुनाव के समय किसानों की कर्जमाफी का नाटक करना पड़ता। किसान बार. बार कहता है कि उसे खेरात की जरूरत नहीं है बल्कि फसल के उचित दाम की जरूरत है। सच्चाई यह है कि दिन.प्रतिदिन खेती की लागत बढ़ती जा रही है लेकिन उस फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है इसी कारण आज किसान भी अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। वह खेती किस काम की जिससे उसकी न्यूनतम जरूरत भी पूरी नहीं हो पा रही हो। चौधरी चरण सिंह के बाद केंद्र में किसी भी किसान नेता को किसान की समस्याओं और उसके समाधानों की चिंता नहीं रही है। किसानों के प्रति हमदर्दी का घडियाली आंस्कू तो सभी नेता बहा लेते हैं लेकिन उनकी ईमानदारी और प्रतिबद्धता हमेशा सदृग्ध दिखाई देती हैं। किसान हमेशा से सरकारों के लिए एक नरम चारा की तरह रहा है। भारतीय किसान की समस्या यह है कि वह जैसे ही एक किसान के रूप में संगठित होना चाहता है राजनेता उसे जतियों की खांचे में बांटकर अपनी चुनावी फसल काट लेते हैं। फिर पाँच साल के लिए बेसहारा छोड़ देते हैं।

विकसित देश अपने किसानों को अधिक से अधिक सब्सिडी मुहैया करा रहे हैं। जबकि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं तीसरी दुनिया के देशों को उनकी सरकारों द्वारा किसानों को दी जा रही सब्सिडी कम करने का दबाव बनाती हैं। भारतीय कृषि विकसित देशों की तुलना में पहले से ही पिछड़ी हुई है और ऊपर से सब्सिडी भी कम मिल रही तो विश्व बाजार में भारतीय किसान इन देशों के किसानों से कैसे बराबरी कर पायेंगे।

साठ के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति अन्न के रूप में भारत को आत्मनिर्भर तो बना दिया किन्तु बाढ़ के वर्षों में उसकी चमक फीकी पड़ गई। ज़मीन भी अपनी खरिंता खोने लगी, भूजल के स्तर में भयंकर गिरावट आई। जल और जमीन जहरीली हो गई, जिसके कारण खाद्यान्नों की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जिस पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल रही, उसी जगह कैन्सर से लोग पीड़ित हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण अत्यधिक कीटनाशक दवाइयों और रासायनिकों के प्रयोग हैं। निः संदेह हरित क्रांति से कुछ वर्षों के लिए खाद्यान्नों की पैदावार बहुत बढ़ गई थी, लेकिन इसने हमारी सब्जियों से आजमाई परंपरागत कृषि प्रणाली पर दूरगामी नकारात्मक प्रभाव भी छोड़ा है। यह हमारे लिए आयातित नयी कृषि प्रणाली थी। इसने कृषि रसायनों के अविवेकपूर्ण उपयोग और सिंचाई की अनिवार्यता से हमारी कृषि संस्कृति में आमूल. चूल परिवर्तन किया। संकर बीजों के प्रवेश ने सब्जियों से किसानों द्वारा विकसित स्थानीय बीजों का स्थान ले लिया।

भारत सरकार ने हटाई

गैर-बासमती और टूटे चावल के निर्यात पर रोक, सितंबर में लगी थी पाबंदी

क्यों लगी थी चावल निर्यात पर पाबंदी?

देश के कुछ राज्यों में बारिश औसत से भी कम होने के कारण धान का बुवाई क्षेत्र घट गया था। इससे चावल का उत्पादन प्रभावित हो गया। इसे देखते हुए सरकार ने थ्रोलू सप्लाय को बढ़ाने के लिए टूटे चावल और जैविक गैर-बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी थी। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने 150 से भी ज्यादा देशों को चावल निर्यात किया था। चावल के वैश्विक व्यापार में भारत की 40 फीसदी भागीदारी है।

फॉर्निन ट्रेड के डायरेक्टोरेट जनरल ने मंगलवार को कहा कि टूटे हुए चावल और जैविक गैर. बासमती चावल के निर्यात पर अब पहले वाले नियम ही चलेंगे। बता दें कि अचानक से लगी रोक के कारण बड़ी मात्रा में चावल का स्टॉक बंदरगाहों पर फंस गया था। सरकार ने मंगलवार को टूटे चावल सहित जैविक गैर-बासमती चावल के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है। सरकार के इस कदम से इस जिनस के निर्यात की खेप को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

निर्यात अब सितंबर में लागू प्रतिबंध से पहले के नियमों द्वारा प्रशासित होगा। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल.सितंबर के दौरान चावल का निर्यात 5.5 अरब डॉलर का रहा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021.22 में यह 9.7 अरब डॉलर का हुआ था।

निर्यात की स्थिति

अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ के पूर्व अध्यक्ष विजय सेतिया ने कहा. भारत सालाना लगभग 10.000.15.000 टन जैविक चावल (बासमती और गैर.बासमती) का निर्यात करता है। पिछले 4.5 वर्षों में जैविक बासमती और गैर.बासमती चावल का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था और सरकार ने इस प्रतिबंध को हटाकर सही कदम उठाया है। भारतीय खाद्य निगम ;एस्सीआई के प्रबंध निदेशक, अशोक के के मीणा ने 23 नवंबर को कहा था कि सरकार नियमित रूप से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य परिदृश्य की निगरानी कर रही है

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने सितंबर की शुरुआत में थ्रोलू बाजार में चावल की उपलब्धता बढ़ाने के मकसद से जैविक गैर.बासमती और टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगा दी थी। थ्रोलू बाजार में चावल की कीमतों में आ रही तेजी को रोकने के लिए सरकार ने इसके निर्यात पर लगाने वाली ड्यूटी को बढ़ाकर 20% करने का फैसला लिया था।

लगाया 20 प्रतिशत शुल्क

सरकार ने थ्रोलू उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से सितंबर की शुरुआत में टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद गैर.बासमती चावल के निर्यात पर 20 प्रतिशत का शुल्क लगाया गया, जिसका उद्देश्य खुदरा बाजारों में कीमतों के बढ़ने के बाद इनकी थ्रोलू आपूर्ति को बढ़ाना था। एक अधिसूचना में, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने मंगलवार को कहा कि जैविक गैर.बासमती टूटे चावल सहित जैविक गैर.बासमती चावल का

और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय कर रही है।

सरकार के फैसले का कंपनी

शेयरों पर असर

सरकार के चावलों के निर्यात से बैन हटाने पर चावल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। चमन लाल सतिया के शेयरों में 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। मौजूदा समय में चमन लाल सतिया का शेयर 2.17 फीसदी की तेजी के साथ 127.30 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

वहीं दूसरी कोहीनूर का शेयर 2.55 फीसदी की तेजी के साथ 54.30 रुपये पर है। जीआरएम ओवरसीज के शेयर 4 फीसदी की तेजी के साथ 360.50 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। वहीं एलटी फूड्स के शेयरों में भी 4 फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है और दाम 115.65 रुपये प्रति शेयर हो गए हैं।



यूके में गेहूं की नई किस्म विकसित, सूखी जमीन पर भी होगी बंपर पैदावार

यूके के वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने गेहूं की एक ऐसी किस्म की खोज की है, जो सूखा प्रतिरोधी है। ऐसे में इसकी कम नमी वाले मिट्टी में भी खेती की जा सकती है। जॉन इन्स सेंटर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने गेहूं के इस किस्म का नाम आरटीएच 1 3 रखा है। इसकी फसल की लंबाई पारंपरिक गेहूं के मुकाबले कम होगी। खास बात यह है कि तेज 1 3 किस्म को सिंचाई के लिए बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ेगी। साथ ही उपज भी अच्छी मिलेगी। शोधकर्ताओं ने बीते 23 नवंबर को प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (पीएसएस) जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित किया था। अध्ययन में कहा गया है कि आरएचटी 1 3 जिन वाले गेहूं की किस्मों को गेहूं की किस्मों में तेजी से पैदा किया जा सकता है। साथ ही पूरे विश्व में इसकी खेती की जा सकती है। इससे किसानों को सूखे मिट्टी में भी कम ऊंचाई वाले गेहूं उगाने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

दरअसल, 1960 के दशक और हरित क्रांति के बाद से, कम ऊंचाई वाले जीनों ने वैश्विक गेहूं की पैदावार में वृद्धि की है, क्योंकि छोटे तने वाले गेहूं का उत्पादन तनों के बजाय अनाज में अधिक निवेश करता है। इससे गेहूं के उत्पादन क्षमता में सुधार भी हुआ है। आरएचटी 13 की बुवाई जमीन के काफी अंदर की जाती है। ऐसे में माना जा रहा था कि इसके बीज अंकुरित नहीं हो सकते हैं। हालांकि, नाए खोजे गए आरटीएच 1 3 बीने जिन ने अंकुर निकलने की इस समस्या पर काबू पा लिया, क्योंकि जिन गेहूं के तने में ऊपर के ऊतकों में कार्य करता है। अंकुर पूरी तरह से उभरने के बाद ही बौनापन तंत्र प्रभावी होता है। जॉन इन्स सेंटर समूह के नेता डॉ. फिलिपा बोलिल ने कहा कि खोज ने प्रजनकों को एक आदर्श अनुवांशिक मार्कर दिया है, ताकि वे अधिक जलवायु लचीला गेहूं पैदा कर सकें। हमने एक नया तंत्र पाया है जो परंपरागत अर्ध. बीने जिन से जुड़े कुछ नुकसानों के बिना कम ऊंचाई वाली गेहूं किस्मों को बना सकता है। वहीं, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (पीएनएस) की कार्यवाही में दिखवाई देने वाले अध्ययन से पता चलता है कि नए अर्ध. बीने जिन के अतिरिक्त कृषि संबंधी लाभों में कठोर उपजी शामिल हो सकते हैं, जो तूफानी मौसम का सामना करने में सक्षम हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे किसानों को शुष्क परिस्थितियों में अधिक गहराई में रोपण करने पर महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। इस शोध के लिए अगला कदम में यह परीक्षण करना होगा कि यह जिन यूके से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक विविध कृषि संबंधी वातावरण में कैसे काम करता है।

वैज्ञानिकों ने समुद्र की सतह से हजारों फीट नीचे रहने वाले काले मूंगे की पांच नयी प्रजातियों का लगाया प्रता

हलधर किसान । (98262 25025) वैज्ञानिकों ने एक रिमोट से नियंत्रित पनडुब्बी का उपयोग करते हुए ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में सतह से 2.500 फीट नीचे रहने वाले काले मूंगे की पांच नई प्रजातियों की खोज की है। काले मूंगों को उथले पानी और 26.000 फीट से अधिक की गहराई तक बढ़ते हुए देखा जा सकता है। कुछ मूंगे 4.000 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। इनमें से कई मूंगे शाखाओं वाले होते हैं और पंखे या झाड़ियों की तरह दिखते हैं, जबकि अन्य चाबुक की तरह सीधे होते हैं। उनके रंगीन उथले पानी के प्रजातियों के विपरीत जो ऊर्जा के लिए सूर्य और प्रकाश संश्लेषण पर भरोसा करते हैं काले मूंगे फिल्टर फीडर अथवा छान कर खाने वाले होते हैं जो छोटे जोलांकटन खाते हैं जो गहरे पानी में प्रचुर मात्रा में होते हैं।

शोधकर्ता ने बताया कि 2019 और 2020 में, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की एक टीम ने ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर का पता लगाने के लिए रिमोट ओशन इंस्टीट्यूट के दूर से संचालित वाहन, सुबास्टियन नामक पनडुब्बी का इस्तेमाल किया।

उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 130 फीट से 6.000 फीट गहरे पानी में रहने वाली मूंगे की प्रजातियों के नमूने एकत्र करना था। अतीत में, इस क्षेत्र के गहरे हिस्सों से मूंगे को ड्रेजिंग और ट्रैलिंग विधियों का उपयोग करके एकत्र किया जाता था जो अक्सर मूंगे को नष्ट कर देते हैं। हमारे दो अभियान ऐसे पहले अभियान थे, जिन्होंने इन विशेष गहरे पानी वाले पारिस्थितिक तंत्रों में एक रोबोट को भेजा जिससे हमारी टीम को गहरे समुद्री मूंगों को उनके प्राकृतिक आवासों में वास्तव में देखने और सुरक्षित रूप से एकत्र करने में मदद मिली। 31 गोता लगाने के दौरान शोधकर्ताओं ने काले मूंगों के 60 नमूने एकत्र किए।

उन्होंने बताया कि रोबर के रोबोटिक पंजों का उपयोग करके रेतिले फर्श या मूंगे की

दीवार से मूंगे को सावधानी से हटाने, मूंगे को एक दबावयुक्त, तापमान-नियंत्रित स्टोरेज बॉक्स में रखा गया और फिर उन्हें सतह पर लाया गया। इसके बाद मूंगे की शारीरिक विशेषताओं की जांच की और उनके डीएनए को अनुक्रमित किए गए।

कई दिलचस्प नमूनों में से पांच नई प्रजातियां थीं, जिनमें से एक को हमने समुद्र की सतह से 2.500 फीट नीचे एक नॉटिलस के खोल पर उगते हुए पाया। इसी तरह उथले पानी के मूंगे जो मछलियों से भरी रंगीन चट्टानों का निर्माण करते हैं काले मूंगे महत्वपूर्ण निवास स्थान के रूप में कार्य करते हैं जहां मछली और अकशेरुकी भोजन करते हैं और शिकारियों से छिपते हैं जो अन्यथा ज्यादातर बंजर समुद्री तल हैं। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया के तट से 2005 में एकत्रित एक काले मूंगे की कॉलोनी जो 2.554 न बदलने वालों का घर था।

हाल के शोध ने एक गहरे समुद्र की तस्वीर को चित्रित करना शुरू किया जिसमें पहले से कहीं अधिक प्रजातियां शामिल हैं।



यह देखते हुए कि दुनिया में काले मूंगों की केवल 300 ज्ञात प्रजातियां हैं, एक सामान्य स्थान पर पांच नई प्रजातियों को खोजना हमारी टीम के लिए बहुत आश्चर्यजनक और रोमांचक था। मूंगों की अवैध कटाई से कई काले मूंगों को खतरा है। इन आकर्षक और दुर्गम आवासों के अच्छे संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए शोधकर्ताओं के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि इन गहराइयों और अलग-अलग प्रजातियों की भौगोलिक सीमाओं में कौन सी प्रजातियां रहती हैं।

हर बार जब वैज्ञानिक गहरे समुद्र का पता

लगाते हैं तो वे नई प्रजातियों की खोज करते हैं। बस अधिक खोज करना सबसे अच्छी बात है कि शोधकर्ता जानकारी की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि वहां कौन सी प्रजातियां रहती हैं और वो किस तरह फैली हैं।

क्योंकि गहरे समुद्र में काले मूंगों के इतने कम नमूने एकत्र किए गए हैं, मूंगों के विकासवादी ट्री के बारे में जानने के लिए भी बहुत कुछ है। जीव विज्ञानी जितनी अधिक प्रजातियों की खोज करते हैं, उतना ही बेहतर हम उनके विकासवादी इतिहास को समझ पाएंगे, जिसमें यह भी शामिल है कि वे कम से

कम चार बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटनाओं से कैसे बचे हैं। शोधकर्ताओं ने कहा उनका अगला कदम समुद्र के तल का पता लगाना जारी रखना है।

शोधकर्ताओं ने अभी तक काले मूंगों की अधिकांश ज्ञात प्रजातियों से डीएनए, एकत्र नहीं किया है। भविष्य के अभियानों में ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में अन्य गहरी मूंगों के लौटने की योजना बना रहे हैं ताकि इन आवासों के बारे में और अधिक सीखना और बेहतर ढंग से उनकी रक्षा करना जारी रखा जा सके। यह शोध जूटवक्सा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

कपास की कीमतों को देखते हुए किसान सतर्क, भंडारण पर दे रहे जोर

हलधर किसान डेस्क.

(98262 25025) । महाराष्ट्र और मध्य कपास उत्पादकों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीजन की बड़े दामों से हुई शुरुआत के बाद कम मिल रहे दामों से किसान निराश नजर आ रहे हैं। नवीजवन आगामी दिनों में अच्छे भाव मिलने की आस में किसान कपास का भंडारण करने पर जोर दे रहे हैं, हालांकि लघु कृषक वर्तमान भाव में ही उपज बेचने को मजबूर हैं।

किसानों का कहना है कि कपास का दाम कम से कम 10 हजार रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। इस समय महाराष्ट्र सहित मध्य के कई जिलों में कपास का दाम 7000 रुपये से लेकर

एकेजरेट 8000 मिलने से हमे मुनाफा छोड़िये लागत तक मुश्किल है निकाल पा रहे है।

कपास का क्विंटल दाम मिल रहा है किसानों को

जलाशय की मंडी में 29 नवंबर को सिर्फ 40 क्विंटल कपास की आवक हुई। जिसका न्यूनतम दाम 7580 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अधिकतम दाम 8470 रुपये प्रति क्विंटल रहा। औसत दाम 8110 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

नांदेड़ में 164 क्विंटल कपास की आवक हुई। जहां न्यूनतम दाम 8400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अधिकतम दाम 8700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। औसत भाव 8560 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

वाशिम मंडी में 65 कपास के क्विंटल की आवक हुई। जिसका न्यूनतम दाम 8400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अधिकतम दाम 8600 रुपये प्रति क्विंटल जबकि औसत दाम 8400 रुपये प्रति क्विंटल मिला।

केंद्र ने तैयार किया बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम

हलधर किसान । (98262 25025) केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) तैयार किया है। इसके समुचित क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्री तोमर ने अधिकारियों से कहा कि देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना व किसानों को उपज के वाजिब दाम दिलाना सरकार का प्रथम लक्ष्य है। इसलिए किसी भी योजना के तहत उन्हें राष्ट्रीय व वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल किया जा सके। किसानों को अधिक पारिश्रमिक मिल सके। सीडीपी से लगभग 10 लाख किसानों और मूल्य श्रृंखला के संबंधित हितधारकों को लाभ होगा। सीडीपी का लक्ष्य लक्षित फसलों के नियंत्रण में लगभग 20 प्रतिशत का सुधार करना तथा क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए क्लस्टर विशिष्ट ब्रांड बनाना है। सीडीपी के माध्यम से बागवानी क्षेत्र में काफी निवेश भी आ सकेगा।

केंद्र में किसानों का हित सर्वोपरि होना चाहिए। उद्देश्य है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड और उत्तराखंड सहित कई राज्यों को भी उनकी केंद्रित/मुख्य फसल के साथ चिन्हित किए गए 55 क्लस्टरों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

किसानों को होगा अधिक फायदा
राज्य मंत्री चौधरी ने कहा कि कार्यक्रम के तहत छोटे व सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने, खेतों में लागू की जाने वाली गतिविधियों का पता लगाने, निगरानी उद्देश्य

थाईलैंड के वैज्ञानिकों की मदद से छत्तीसगढ़ में मछलियाँ के जेनेटिक्स पर रिसर्च शुरू, उन्नत किस्मों होंगी विकसित

हलधर किसान। (98262 25025) छत्तीसगढ़. मछली को कृषि बीज उत्पादन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। अब यहां मछली अनुसंधान के लिए निजी क्षेत्र की इकाईयां भी आगे आ रही हैं। राष्ट्रीय मातृस्यकी विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी डॉ. सी सुवर्णा यहां दो दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं।

डॉ. सुवर्णा ने मछली पालन उरु क की एका जेनेटिक केन्द्र का दौरा किया। सिमगा विकासखण्ड के ग्राम बाईकोनी में स्थित प्रतिदिन 100 टन उत्पादन की क्षमता वाले वृहद निजी मत्स्य आहार केन्द्र का शुभारंभ भी किया। छत्तीसगढ़ में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त की।

राजधानी रायपुर से लगे ग्राम रामपुर में थाईलैंड के वैज्ञानिकों के तकनीकी सहयोग से मछली अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है। गौरतलब है कि एका जेनेटिक के इस केन्द्र की स्थापना एम हेचरी रायपुर एवं मनीत गुप थाईलैंड के संयुक्त प्रयास से की गई है। अनुसंधान केन्द्र में थाईलैंड के वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ ही प्रशिक्षण भी देंगे। लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में फैले इस अनुसंधान केन्द्र में मछली के जेनेटिक्स पर अनुसंधान के साथ साथ तिलापिया मछली बीज का उत्पादन भी किया जा रहा है। इसके अलावा यहां मत्स्य कृषकों को मछली पालन के अत्याधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाला छत्तीसगढ़ और देश में अपने तरह का यह पहला केन्द्र है।

उन्नत किस्म के मछली के बीज की आपूर्ति हो सकेगी

ग्राम रामपुर में स्थापित इस अनुसंधान केन्द्र से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के किसानों को उन्नत किस्म के मछली के बीज की आपूर्ति हो सकेगी। इससे छत्तीसगढ़ मछली उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से प्रगति करेगी। इसके इलावा वृहद मत्स्य आहार केन्द्र के प्रारंभ होने से प्रदेश के किसानों को स्थानीय स्तर पर कम दर पर मछली का आहार प्राप्त हो सकेगा।

डीएमएफ़े 40 प्रतिशत अनुदान मिला है

डॉ. सुवर्णा ने सिमगा विकासखण्ड के ग्राम खेरवारी महिला स्व. सहायता समूह द्वारा बंद हो चुके खदानों में केज कल्चर विधि से किये जा रहे मछली पालन का भी निरीक्षण किया। खास बात यह है कि समूह द्वारा यहां मछली पालन के लिए 12 केज तैयार किये गए हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत 36 लाख रूपए है। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 60 प्रतिशत और डीएमएफ़े 40 प्रतिशत अनुदान दिया गया है। अपने प्रवास के दौरान रायपुर जिले के तिरवा विकासखण्ड के ग्राम पीकरीडीह स्थित वृहद बायोफ्लोक् यूनिट का भी निरीक्षण किया।

मध्यप्रदेश में शुरू हुई धान की खरीद, किसान इन बातों का रखें ध्यान



हलधर किसान

(98262 25025)। मप्र में धान की खरीद शुरू हो गई है। 28

नवंबर से 16 जनवरी तक धान की खरीदी की जाएगी। राज्य में

धान का समर्थन मूल्य 2040

प्रति क्विंटल तय किया गया है।

जबकि किसान 1 दिसंबर से 31

दिसंबर तक ज्वार, बाजरा, बेच

सकेंगे। ज्वार का 2970 रूपए

प्रति क्विंटल, वहीं बाजरा का

2350 रूपए प्रति क्विंटल तय

किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार इस बार प्रदेश के ई.प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर 8 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अनुमान



नीलामी नहीं, अब मछली पालन के लिए 10 वर्षीय पट्टे पर दिए जाएंगे तालाब और जलाशय

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन मछली पालन नीति में मछुआरा के हितों को ध्यान में रखते हुए संशोधन को मंजूरी दी गई।

मछुआ समुदाय के लोगों की मांग और उनके हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से नवीन मछली पालन नीति में तालाब और जलाशयों को मछली पालन के लिए नीलामी करने के बजाय लीज पर देने के साथ ही वंशानुगत परंपरागत मछुआ समुदाय के लोगों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। तालाबों एवं सिंचाई जलाशयों के जलक्षेत्र आबंदन सीमा में 50 फीसद की कमी कर ज्यादा से ज्यादा मछुआरों को रोजी.रोजगार से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। प्रति सदस्य के मान से आबंटित जलक्षेत्र सीमा शर्त घटाने से लाभान्वित मत्स्य पालकों की संख्या दोगुनी हो जाएगी।

संशोधित नवीन मछली पालन नीति के अनुसार मछली पालन के लिए तालाबों एवं

सिंचाई जलाशयों की अब नीलामी नहीं की जाएगी, बल्कि 10 साल के पट्टे पर दिए जाएंगे। तालाब और जलाशय के आबंटन में सामान्य क्षेत्र में ड्रैमर, निषाद, केबट, कहार, कहरा, मल्लह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को तथा अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। मछुआ से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो अपनी अजीबिका का अर्जन मछली पालन, मछली पकड़ने या मछली बीज उत्पादन का कार्य करता हो, के तहत वंशानुगत परंपरागत धीवर, निषाद, कहार, कहरा, मल्लह को प्राथमिकता दिया जाना प्रस्तावित है।

इसी तरह मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति अथवा मछुआ व्यक्ति को ग्रामीण तालाब के मामले में अधिकतम एक हेक्टेयर के स्थान पर आधा हेक्टेयर जलक्षेत्र तथा सिंचाई जलाशय के मामले में चार हेक्टेयर के स्थान पर दो हेक्टेयर जलक्षेत्र प्रति सदस्य प्रति व्यक्ति के

मान से आबंटित किया जाएगा। मछली पालन के लिए गठित समितियों का ऑडिट अभी तक सिर्फ सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता था। अब संशोधित नवीन मछली पालन नीति में सहकारिता एवं मछली पालन विभाग की संयुक्त टीम ऑडिट की जिम्मेदारी दी गई है।

त्रि.स्त्रीय पंचायत व्यवस्था अंतर्गत शून्य से 10 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के तालाब एवं सिंचाई जलाशय को 10 वर्ष के लिए पट्टे पर आबंटित करने का अधिकार ग्राम पंचायत का होगा। जनपद पंचायत 10 हेक्टेयर से अधिक एवं 100 हेक्टेयर तक एंव जिला पंचायत 100 हेक्टेयर से अधिक एवं 200 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक, मछली पालन विभाग द्वारा 200 हेक्टेयर से अधिक एवं 1000 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के जलाशय, बैराज को मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को पट्टे पर देगा। नगरीय निकाय अंतर्गत आने वाले समस्त जलक्षेत्र नगरीय निकाय के अधीन होंगे, जिसे शासन की नीति के अनुसार 10 वर्ष के लिए लीज पर आबंटित किया जाएगा।

डीएपी की कमी होने पर वैकल्पिक उर्वरकों का करें प्रयोग

अनुसार एक बैग डीएपी या 3 बैग एसएसपी या डेढ़ बैग एनपीके 12.32.16 का प्रयोग करके फास्फोरस की आपूर्ति पूर्ण कर सकते हैं। गत वर्ष सितंबर से नवम्बर माह तक प्रदेश में 2 लाख 78 हजार मीट्रिक टन डीएपी बिक्री हुई थी, जबकि इस वर्ष सितंबर से नवम्बर माह 21 नवम्बर तक प्रदेश में 3 लाख 6 हजार मीट्रिक टन डीएपी की बिक्री हो चुकी है।

केंद्र सरकार द्वारा राज्य में प्रतिदिन 2 से 3 हजार मीट्रिक टन डीएपी, एनपीके उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा खाद की बिक्री व्हाइट ऑफ सेल (पीओएस) मशान से की जानी सुनिश्चित की है। किसान संयम रखते हुए शांति पूर्वक खाद की खरीद करें ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले।

हलधर किसान। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों के नाम संदेश जारी करते हुए कहा कि डीएपी की कमी होने पर वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग करें। प्रदेश सरकार द्वारा 7 पर्याप्त डीएपी खाद उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। किसान गेहूँ की बिजाई में डीएपी खाद के स्थान पर एसएसपी व एनपीके का प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रदेश में वर्तमान में 23 हजार मीट्रिक टन एसएसपी एवं 7 हजार मीट्रिक टन एनपीके स्टॉक के रूप में उपलब्ध है। डीएपी खाद के स्थान पर गेहूँ की बिजाई में दूसरे उर्वरक भी प्रयोग किये जा सकते हैं।

हिसार स्थित चौ.चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिश के

प्रतियां पाने, लेख प्रकाशन के लिए संपर्क करें

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए शोध, अनुसंधान, कृषि सफलताओं, नवाचारों, योजनाओं के प्रकाशन के माध्यम से प्रयासरत है। हलधर किसान, राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र की प्रतियां प्राप्त करने के साथ ही कृषि, पशुपालन, बागवानी, अनुसंधान जैसे क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, शोध, खेती में नवाचार जैसे लेख प्रकाशन करना चाहते हैं तो हमें वाट्सएप नंबर- 8817402860, 94254 89337 पर भेजे सकते हैं। हम आपका लेख प्रमुखता से फोटो सहित उचित स्थान पर प्रकाशित करेंगे अपना नाम, डाक पता और फोन नंबर सहित संपर्क करें।

चीन ने तैयार की चावल की नई किस्म, एक बार करें खेती और 8 साल तक काटते रहें फसल

नेचर सस्टेनेबिलिटी जर्नल के शोध के अनुसार, इस बारहमासी चावल उगाने से पर्यावरण को भी काफी लाभ पहुंचा है

हलधर किसान।
(98262 25025)

चीन ने हाल ही में पीआर23

नामक चावल की एक किस्म

विकसित की है। इस किस्म की

खासियत है कि इसकी हर साल

रोपाई करने की जरूरत नहीं है।

एक बार पीआर23 की खेती शुरू

करने के बाद आप इससे चार से

आठ सालों तक फसल काट

सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के

मुताबिक, पीआर23 की जाई बहुत

मजबूत होती है। ऐसे में पीआर23

फसल की कटाई करने के बाद

अपने आप उसकी जाई से नाए

पौधे निकल आते हैं। ये नाए पौधे

भी पहले की तरह ही तेजी से बढ़ते

हैं और समग्र पीएल देते हैं।

न्यूज वेबसाइट मिंट के मुताबिक, युनान

विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अफ्रीका के

एक जंगली बारहमासी किस्म के गैलर वाणिक

चावल औरिजा सेंटिवा के क्रॉस ब्रॉडिंग द्वारा

पीआर23 किस्म को विकसित किया है।

पीआर23 अपनी गुणवत्ता के साथ साथ

पैदावार के मामले में भी नंबर वन है। इसकी

उत्पन्न 6.8 टन प्रति हेक्टेयर है, जो नियमित

सिंचित चावल के बराबर है। वहीं, इसे

परंपरिक चावलों के मुकाबले उगाना भी काफी

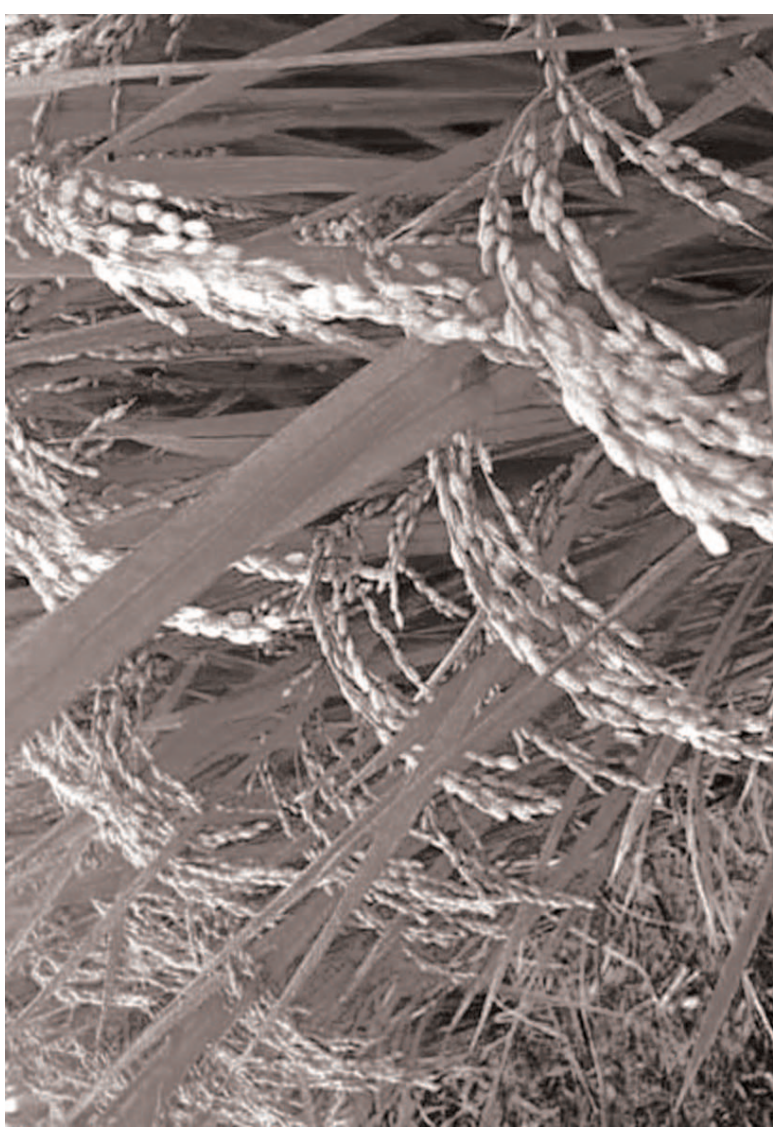
सस्ता है क्योंकि इसमें श्रम के साथ साथ

बीज और रासायनिक उर्वरकों की भी जरूरत

बहुत कम होती है। पिछले साल दक्षिणी चीन में

44,000 से अधिक किसानों ने इस किस्म की

खेती की थी। इससे उन्हें बंपर उपज मिली।



इनपुट लागतों में 49 प्रतिशत की बचत हुई है

नेचर सस्टेनेबिलिटी जर्नल के शोध के अनुसार, इस बारहमासी चावल उगाने से पर्यावरण को भी काफी लाभ पहुंचा है। पानी में वृद्धि के साथ एक टन कार्बनिक कार्बन (प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष) भी मिट्टी में जमा हुआ है, जिससे चावल के पौधों को भी पर्याप्त इंधन वहीए किसानों द्वारा भी इस बारहमासी किस्म को पसंद किया जा रहा है। इसकी खेती शुरू करने से किसानों को हर सीजन में श्रम में 58 प्रतिशत और अन्य इनपुट लागतों में 49 प्रतिशत की बचत हुई। वहीं, शोधकर्ताओं का दावा है कि यह आजीविका में सुधार, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और अन्य अनाजों पर अनुसंधान को प्रेरित करके खेती को बदल सकता है।

नई किस्म की खोज क्यों महत्वपूर्ण है?

बता दें कि युनान अकादमी वर्ष 1970 से ही इस तरह की चावल की किस्म पर काम कर रहा था, पर उसे शुरूआती दशक में सफलता नहीं मिली। इसके बाद, अकादमी ने 1990 के दशक की शुरुआत में भी बारहमासी चावल पर काम शुरू किया। 1995 और 2001 के बीच अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने एक परियोजना शुरू कीए जहां चीन के एक युवा मास्टर छात्र फेंगथी हू ने बारहमासी चावल प्रजनन पर काम किया। निधि कटौती के कारण 2001 में परियोजना को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद हू ने द लैंड इंस्टीट्यूटए कंसास और यूएस के सहयोग से युनान विश्वविद्यालय में शोध जारी रखा और अंत में उसे पीआर23 कीस्म विकसित करने में सफलता मिली। ऐसे में पहली किस्म 2018 में चीनी उत्पादकों के लिए जारी की गई थी।

भारतीय चाय का आयात नहीं कर रहा है ईरान, निर्यातकों ने जताई चिंता

हलधर किसान। कोलकाता: चाय निर्यातकों ने बुधवार को कहा कि भारतीय चाय का एक प्रमुख खरीदार देश ईरान खरीद के लिए अनिवाध्य प्रयत्न (प्रोफार्मी) नहीं भर रहा है और उसे रूपए में भुगतान समझौते को अंतिम रूप दिए जाने का इंतजार है। वर्ष 2021 में ईरान ने भारत से दो करोड़ 61.8 लाख किलोग्राम चाय का आयात किया था जो 2020 में इस फारस की खाड़ी के देश द्वारा किए गए तीन करोड़ 37.5 लाख किलोग्राम के आयात की तुलना में काफी कम था। भारतीय चाय संघ (आईटीए) के महासचिव अरिजीत राहा ने कहा, हम रिपोर्ट देख रहे हैं कि ईरान ने भारत से चाय का आयात बंद कर दिया है। हमने चाय बोर्ड को सूचित कर दिया है जो इस मामले को देख रहा है। उन्होंने कहा, हमें पता लगा है कि पंजीकरण या चालान के ऑर्डर से संबंधित कुछ मुद्दे हैं जो ईरानी आयातकों द्वारा जारी नहीं किए जा रहे हैं। निर्यात विपणन परामर्शदाता संजय मुखर्जी ने कहा कि उनके ईरानी संपर्कों ने उन्हें बताया था कि वे खरीदारी में देरी कर रहे हैं। रूपए के भुगतान का समझौता किया जा रहा है। जिससे तीसरे देशों के माध्यम से व्यापार करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

सरकार युवा पीढ़ी को कृषि क्षेत्र में प्रवेश के लिए कर रही प्रोत्साहित: केंद्रिय कृषि मंत्री तोमर

फिफकी सस्टेनेबल एग्रिकल्चर समिट और अवार्ड कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर



करोड़ रुपये के खर्च से 10 हजार नए एफपीओ का गठन करने की स्कीम लाने सहित अनेक कदम ठोस उठाए हैं। केंद्र सरकार छोटे किसानों को रियायती ब्याज पर अल्पकालिक ऋण प्रदान कर रही है, जिसकी सीमा बढ़कर 18 लाख करोड़ रूपए की गई है। देशभर में कृषि बुनियादी ढांचे में गैस भरने पर भी केंद्र सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए सरकार ने एक लाख करोड़ रूपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित किया है, वहीं मशुपालन, मत्स्यपालन

करोड़ रुपये के खर्च से 10 हजार नए एफपीओ का गठन करने की स्कीम लाने सहित अनेक कदम ठोस उठाए हैं। केंद्र सरकार छोटे किसानों को रियायती ब्याज पर अल्पकालिक ऋण प्रदान कर रही है, जिसकी सीमा बढ़कर 18 लाख करोड़ रूपए की गई है। देशभर में कृषि बुनियादी ढांचे में गैस भरने पर भी केंद्र सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए सरकार ने एक लाख करोड़ रूपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित किया है, वहीं मशुपालन, मत्स्यपालन

मार्च तक 3.71 लाख किसानों को ऋण देने का लक्ष्य: सहकारिता सचिव श्रेया गुहा

हलधर किसान (98262 25025) ।

जयपुर: सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने जयपुर के अपेक्स बैंक सभागार में केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 1.29 लाख किसानों को कुल 233 करोड़ रुपये का फसल ऋण दिया गया है। मार्च 2023 तक 3.71 लाख नए किसानों को सहकारी समितियों से जुड़े जाएंगे और उन्हें फसल ऋण दिया जाएगा। उन्होंने एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक को फसल ऋण के वितरण के साथ साथ सहकारी समितियों से जुड़े नए किसान सदस्यों की साप्ताहिक समीक्षा करने का भी निर्देश दिया।

गुहा ने कहा कि योग्य किसानों को कृषि और मध्यावधि ऋण देना भी प्राथमिकता होनी चाहिए, साथ ही किसानों के लिए नाबाई कार्यक्रमों का उपयोग करके इन ऋणों की वितरण प्रक्रिया को और आसान बनाना है, ताकि उनकी स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उनके अनुसार 26.92 लाख किसानों को 25 नवंबर तक बिना ब्याज के 12.811 करोड़ रुपये का फसल ऋण दिया गया। 45 दिनों का कौशल-आधारित प्रशिक्षण

प्रमुख सचिव सहकारिता ने कहा कि पहले किसान देश के सहकारी बैंकों से केवल कृषि से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ही ऋण प्राप्त कर पाते थे। कृषि के अलावा अन्य परियोजनाओं के लिए ऋण लेना बहुत चुनौतीपूर्ण हुआ करता था, लेकिन अब कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए नाबाई (नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) से 20.25 लाख रुपये के बीच वित्तीय सहायता मिल सकती है।

केंद्र सरकार इस योजना के तहत ऋण के बोझ को कम करने के लिए 36 से 44 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करती है, जो कि योजना की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। यदि पांच आवेदकों का समूह इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करता है तो एक करोड़ रुपये तक का ऋण मुहैया कराया जा सकता है। यह कार्यक्रम योग्य किसानों, युवा उद्यमियों और पेशेवरों को 45 दिनों का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। नियमों के मुताबिक, सामान्य वर्गों के आवेदकों को 36 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलती है, जबकि एएससी.एसटी और महिला उम्मीदवारों को 44 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलती है।

गुहा ने कहा कि योग्य किसानों को कृषि और मध्यावधि ऋण देना भी प्राथमिकता होनी चाहिए, साथ ही किसानों के लिए नाबाई कार्यक्रमों का उपयोग करके इन ऋणों की वितरण प्रक्रिया को और आसान बनाना है, ताकि उनकी स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उनके अनुसार 26.92 लाख किसानों को 25 नवंबर तक बिना ब्याज के 12.811 करोड़ रुपये का फसल ऋण दिया गया। 45 दिनों का कौशल-आधारित प्रशिक्षण

खेती को आसान बनाएगी जुताई रहित खेती

(नो-टिल फार्मिंग) कम लागत में मिलती है बंपर पैदावार

हलधर किसान 1 (98262 25025)

बदलते वक्त के साथ खेती करने की तकनीकों में भी बदलाव हो रहा है। आमतौर पर किसान फसल बुवाई से पहले कई बार खेत की जुताई करते हैं, जुताई के लिए ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कई बार ज्यादा जुताई करने के दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। ऐसे में अब किसानों ने नो-टिल फार्मिंग की तकनीक अपनाई है। यह तकनीक जुताई रहित खेती है। इस तकनीक में भूमि को बिना जोते ही कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। यह कृषि की नई तकनीक है, जिससे किसानों को अच्छा लाभ मिलता है। आईए जानते हैं जुताई रहित खेती, इसके लाभ व नुकसान के बारे में।

जुताई रहित खेती से लाभ

बुवाई में कठिनाई, फसल कटाई के बाद खेत में मौजूद मिट्टी ठोस हो जाती है। जिससे दूसरी फसल की बीज बुवाई में मुश्किल होती है। शकनाशी का उपयोग कई बार फसलों के बीच में जंगली पौधों को हटाने के लिए किसान शकनाशी का उपयोग करते हैं जो अच्छे नहीं होता। लेकिन खेत की जुताई के समय यह समस्या नहीं आती।

जुताई रहित खेती के प्रमुख सिद्धांत

जुताई रहित खेती का सबसे पहला सिद्धांत है खेतों में जुताई न करना, न ही मिट्टी को पलटना, ऐसी तकनीक में भूमि खुद स्वाभाविक रूप से पौधों की जड़ों के प्रवेश व केंचुए, छोटे प्राणियों और सूक्ष्म जीवाणुओं के जरिए जुताई कर लेती है।

दूसरे सिद्धांत है कि किसी भी तरह की खाद या रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न करें। जोतने व उर्वरकों के प्रयोग से पौधे

कमजोर होते हैं और कीट असंतुलन की समस्याएं बढ़ती हैं।

तीसरा सिद्धांत है सतह पर जीवांश अवशेष रहना, जीवांश अवशेष को पहले एकत्रित किया जाता है। फिर इस कूड़े को जमीन की सतह पर बिछा दिया जाता है। यह खेत में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखता है और जीव-जंतुओं के लिए खाद्य पदार्थ का काम करता है। यह डी कंपोस्ट होता चला जाता है। इसी से खाद बन जाती है। इससे पौधों में खरपतवार भी नहीं लगता।

चौथा सिद्धांत है फसल चक्र अपनाना, यानि एक फसल के उत्पादन के बाद बिना जुताई के ही दूसरी फसल की बुवाई कर देना। पांचवा सिद्धांत है कि खेत में निर्राई, गुड़ाई न की जाए। इसका सिद्धांत है कि खरपतवार को पूरी तरह समाप्त करने की बजाए नियंत्रित किया जाना चाहिए, कम मात्रा में खरपतवार मिट्टी को उर्वर बनाने में सतुलन स्थापित करने में सहयोगी होते हैं।



जुताई रहित खेती

जुताई रहित खेती के कई फायदे हैं। खेत की प्रमुख फसल की कटाई के बाद बिना जुताई के ही बची हुई मिट्टी में फसल बो देते हैं। ऐसे में पुरानी फसलों के अवशेष से नई फसल पोषण लेती है। इस तकनीक के जरिए आप चना, मक्का, धान, सोयाबीन जैसे फसलें उगा सकते हैं।

जुताई रहित खेती के लाभ

भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, भूमि का उपरदन बहुत कम होता है। फसलों की उत्पादकता बढ़ती है। सिंचाई के अंतराल में वृद्धि होती है, भूमि में नमी बनी रहती है। भूमि के जलस्तर में सुधार होता है, भूमि की जलधारण क्षमता बढ़ती है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। जुताई न होने से समय और धन की बचत होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होती है, लागत में भी कमी आती है। भूमि के अंदर और बाहर पाए जाने वाले उपयोगी सूक्ष्म जीवों को क्षति नहीं पहुंचती। जुताई रहित कृषि से जैविक, रासायनरहित शुद्ध उत्पाद मिलते हैं, जिनकी बाजार में अच्छी डिमांड होने से आय बढ़ती है। कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में कमी आती है। पराली जलाने की घटनाओं में कमी आती है।

19 दिसंबर को लाभकारी मूल्य को लेकर दिल्ली में गरजेंगे किसान

भाकिस 'गर्जना रैली' से कटेगा किसान शक्ति का प्रदर्शन



आधारित लाभकारी मूल्य की मांग कर रहा है। भारतीय किसान संघ की ओर से दिल्ली में आयोजित होने वाली किसान गर्जना रैली में जोधपुर प्रांत से 15 हजार किसान भाग लेंगे। प्रांत से रेल, बसों और निजी वाहनों से किसान दिल्ली पहुंचेंगे।

भारतीय किसान संघ के हिमाचल प्रदेश महामंत्री सुरेश ठक्कर ने कहा है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में संघ 19 दिसम्बर को किसान गर्जना रैली करने जा रहा है। इसमें हिमाचल से भी इसमें हजारों किसान भाग लेंगे। भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश के सभी जनापद में 1 से 10 दिसम्बर तक ग्राम

हलधर किसान। एक बार फिर से दिल्ली में किसानों का विशाल विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। दरअसल, भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में 19 दिसंबर को देशभर के किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान गर्जना रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। संगठन की ओर से इसमें देशभर के 550 जिलों से दो लाख से अधिक किसानों के शामिल होने की संभावना जताई गई है।

जयपुर में भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष दत्तात्रय बटेसर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फसलों की बढ़ती उत्पादन लागत व लागत से नीचे फसल बिकने से किसानों पर बढ़ते कर्ज चिंता का विषय है। इसके समाधान के लिए किसान गर्जना रैली की घोषणा की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ किसानों को लागत आधारित लाभकारी मूल्य दिलाने को लेकर लगातार प्रयासरत रही है। राजस्थान के भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंड ने इस विषय में बात करते हुए बताया कि देशभर के किसान फसलों के लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर 19 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेंगे।

जयपुर प्रांत महामंत्री सांवरमल सोलेट ने बताया कि किसान गर्जना रैली के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय फसलों के लागत

हड़ताल का असर: पंजाब में रोकी धान की खरीद, किसानों ने जताई नाराजगी

हलधर किसान (98262 25025)। और बकाया राशि का भुगतान करें। कहा जा रहा है कि फूड सप्लाय विभाग के कर्मचारी पिछले एक ह. व. से हड़ताल पर हैं। वहीं, हड़ताल खत्म करने के लिए सरकार फूड एंड सप्लाय विभाग के कर्मचारियों को मना रही है। इसके लिए फूड सप्लाय मंत्री लालचंद कटारूचक ने यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और हड़ताल खत्म करने का अनुरोध किया। हड़ताल खत्म करने का आग्रह करते हुए मंत्री ने भरोसा दिया कि किसी भी निर्दोष से धमकेशाही नहीं होगी। हालांकि, इसके बाद भी कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म नहीं की।

जल्द से जल्द धान की खरीद फिर से शुरू करे

1.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है

जानकारी के अनुसार पंजाब में अभी तक 1.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जबकि, सरकार ने 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का लक्ष्य बना रखा है। पंजाब में नेशनल फूड से टी ऐक्ट के तहत अनाज प्राप्त करने वाले 16 लाख से अधिक लोगों को आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर इसी तरह से हड़ताल जारी रही तो तो गिलों में तैयार किए गए चावल को खीकार करने में भी देरी होगी। ऐसे में राज्य सरकार भी भुगतान करने में देरी करेगी।



निति आयोग के सीईओ ने किसानों की आय बढ़ाने दिया सुझाव

हलधर किसान. (98262 25025) नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) परमेश्वरन अय्यर ने भारतीय उद्योग परिषद के सेमिनार में कहा कि खाद्य प्रसंस्करण न सिर्फ अर्थव्यवस्था की सेहत और लोगों के लिए जरूरी क्षेत्र है बल्कि यह किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। इसके साथ ही पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ रोजगार के अक्सर बढ़ाने लिये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है क्योंकि यह सबसे ज्यादा नौकरियां देता है। कृषि क्षेत्र में प्राथमिक प्रसंस्करण बढ़ाने की जरूरत है। सरकार ने इस संबंध में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना सहित कई पहल की है। सरकार ने इस संबंध में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा भोजन उत्पादन के तरीकों में काफी बदलाव आया है। भारत से खाद्य प्रसंस्कृत वस्तुओं के पहले से हो रहे निर्यात को और बढ़ाने की जरूरत है।

रोकनी होगी खाने की बर्बादी

अय्यर ने कहा. दुनियाभर से बहुत लंबी और जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं के जरिये भोजन आता है। यह सबको कवर करता है। चाहे वह पशुपालन हो या कृषि, मत्स्य पालन, भंडारण, खुदरा परिवहन या फिर वितरण। इसलिए प्रसंस्करण के जरिये हमें खाने की बर्बादी को रोकने की जरूरत है। इससे हर साल अरबों की बचत होगी। दुनियाभर में लाखों लोगों को कुपोषण से बाहर निकालने में भी मदद मिलेगी।

हमारे किसान यूरोपीय किसानों की तरह नहीं, जमीनी हकीकत को पहचानिए: सुप्रीम कोर्ट



हलधर किसान. (98262 25025) दिल्ली. आनुवंशिक रूप से मॉडिफाई की गई (जीएम) फसलों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की चिंता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या जीएम सरसों की पर्यावरण मंजूरी देने के पीछे कोई मजबूत कारण रहा है कि ऐसा न करने से देश असफल हो जाएगा? शीर्ष अदालत ने कहा कि भारतीय किसान अपने पश्चिमी समकक्षों के उलट साक्षर नहीं हैं और वे 'कृषि मेला' और 'कृषि दर्शन' जैसे आयोजनों के बावजूद जीन और यूटेशन के बारे में नहीं समझ पाते हैं, जो यह एक जमीनी हकीकत है।

केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों द्वारा जीएम फसलों का विरोध वैज्ञानिक तर्क पर आधारित होने के बजाय वैचारिक है। पर्यावरण मंत्रालय के तहत गठित जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) ने गत 25 अक्टूबर को ट्रांसजेनिक सरसों हड्डिबिड किस्म डीएमएच.11 की पर्यावरणीय मंजूरी दी थी। न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी और न्यायमूर्ति बीबी नारत्ता की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण से कहा कि जिस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए वह यह है कि क्या जीएम सरसों के पर्यावरणीय मंजूरी के कारण कोई अपरिवर्तनीय परिणाम होगा।

केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों द्वारा जीएम फसलों का विरोध वैज्ञानिक तर्क पर आधारित होने के बजाय वैचारिक है। पर्यावरण मंत्रालय के तहत गठित जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) ने गत 25 अक्टूबर को ट्रांसजेनिक सरसों हड्डिबिड किस्म डीएमएच.11 की पर्यावरणीय मंजूरी दी थी। न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी और न्यायमूर्ति बीबी नारत्ता की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण से कहा कि जिस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए वह यह है कि क्या जीएम सरसों के पर्यावरणीय मंजूरी के कारण कोई अपरिवर्तनीय परिणाम होगा।

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वाई नंबर 5, खरगोन से प्रकाशित, संपादक विवेक जैन। Title Code. MPHIN/2022/37675, मोबा. नं.98262 25025, 94254 89337 (समस्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा।)

कहा- खेतों के स्तर पर ही प्राथमिक प्रोसेसिंग बढ़ाने की आवश्यकता



कुछ गंभीर चुनौतियां भी

उन्होंने कहा, खासतौर पर पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सुधार के बावजूद हमें इस दिशा में लंबा रास्ता तय करना है। साथ ही, किसानों को बेहतर फसल पद्धतियों की ओर ले जाना होगा। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत अन्य देशों की तरह उन्नत नहीं है। डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने की जरूरत है। इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को भी सुझाव देना चाहिए।

आरएंडडी को बढ़ावा देने की जरूरत

नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने सीआईआई के कार्यक्रम में कहा, इस समय शोध एवं विकास (आरएंडडी) गतिविधियों को बढ़ावा देने की जरूरत है। यह समय भारत के लिए उन्नत सामग्रियों के स्वदेशी स्तर पर विकास के लिए मुफ्रीद है। इस तरह, आयात पर निर्भरता भी कम की जा सकती है। उन्नत सामग्रियां प्रौद्योगिकी को संक्षम बनाने का काम करती हैं। इस क्षेत्र में क्रांति लाने में मशीन लर्निंग और नए प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स के निर्यात बढ़ाने पर भी जोर दिया।

ओडिशा में होगी जैविक कॉफी की खेती, सरकार ने बनाया रोडमैप

हलधर किसान.
(98262 25025)

ओडिशा सरकार ने अगले पांच वर्षों में हजारों हेक्टेयर में जैविक कॉफी उगाने की योजना बनाई है। इस बात की पुष्टि खुद राज्य कृषि उत्पादन आयुक्त प्रवीण कुमार जोना की हैं। उन्होंने कहा है कि ओडिशा सरकार ने अगले पांच वर्षों में 10,000 हेक्टेयर में जैविक कॉफी उगाने की योजना बनाई है। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर कॉफी बागान हैं, हमने भी कॉफी बागानों के साथ अच्छा काम किया है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि जैविक कॉफी की खेती से किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि कोरापुट में हमें उच्च गुणवत्ता वाली अरोबिका कॉफी मिलती है। जेना ने कहा कि हमने अगले कुछ वर्षों में 10,000 हेक्टेयर कॉफी बागान स्थापित करने का प्रयास किया है। सरकार की यही कोशिश है कि ओडिशा को देश में जैविक कॉफी उत्पादक राज्य के रूप में पहचान दिलाई जाए, वहीं, कॉफी बोर्ड के अनुसार आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्व के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में कुल कॉफी फसल क्षेत्र का लगभग 21 प्रतिशत हिस्सा है। पारंपरिक क्षेत्रों में 3.68 लाख हेक्टेयर की तुलना में 2021.22 में गैर पारंपरिक क्षेत्रों में 99.380 हेक्टेयर में कॉफी उगाई गई थी।

इन जगहों को डिजाइन द्वारा जैविक बनाया जाए

आंध्र प्रदेश में 94.956 हेक्टेयर कॉफी भूमि है, जबकि ओडिशा में 4.424 हेक्टेयर



100 यूनिट तक मिलेगी फ्री बिजली, आधार से लिंक करना होगा कनेक्शन

तमिलनाडु सरकार प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। सरकार के ऐलान के बाद प्रदेश में उन उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी, जिनका बिजली कनेक्शन आधार से लिंक किया गया है। बिना आधार वाले बिजली कनेक्शन को यह सुविधा नहीं दी जाएगी। अगर आपने अभी तक अपना बिजली कनेक्शन आधार से नहीं जुड़वाया है, तो जल्द ही अपने इस काम को पूरा करे और सरकार को इस बेहतरीन सुविधा का लाभ उठाएं।

उल्लेखनीय है कि सरकार उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक फ्री बिजली की सुविधा देने के लिए आधार कार्ड को कनेक्शन से जोड़ना शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया 28 नवंबर 2022 से शुरू हो चुकी है, लेकिन इस दौरान सरकार के पास कई तरह की शिकायतें भी पहुंच रही हैं कि बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा सही तरीके से उनका आधार लिंक नहीं किया जा रहा है और उन्हें पूरे पुरे दिन लाइन में खड़े रहना पड़ता है। ग्राहकों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए सरकार ने तमिलनाडु बिजली विभाग के लिए निर्देश दिए हैं। सरकार की इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए जो भी उपभोक्ता अपना आधार बिजली कनेक्शन से लिंक करना आते हैं, उनके लिए बेटने की सही व्यवस्था होनी चाहिए। जगह कम पड़ने पर शांमियाना लगाए जाएं। काउंटेस की निगरानी करने के लिए टीए/सीए/सीई स्तर के स्टाफ की ड्यूटी लगाएं। बिजली विभाग के कर्मचारियों को ग्राहकों को आधार लिंक व 100 यूनिट की पूरी सुविधा के बारे में बताएं। अगर काउंटर पर कंप्यूटर धीमें चल रहे हैं, तो अतिरिक्त कंप्यूटर लगाएं और कार्य की जितना हो सके जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। ताकि ग्राहकों को इसके लिए अधिक इंतजार न करना पड़े।

और उत्तर पूर्व में 4.695 हेक्टेयर भूमि है। ओडिशा में केवल अरोबिका कॉफी उगाई जाती है, जबकि आंध्र और उत्तर पूर्व में रोबस्टा कॉफी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। साथ ही ओडिशा के आदिवासी समुदाय भी कॉफी की खेती करते हैं। अधिकांश जनजातीय क्षेत्र डिफॉल्ट रूप से जैविक खेती करते हैं। वहां रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता है। जेना ने समझाया कि हालांकि, हम चाहते हैं कि कॉफी के विपणन के लाभ का लाभ उठाने के लिए अब इन जगहों को डिजाइन द्वारा जैविक बनाया जाए। सरकार बड़े पैमाने पर खेती को स्वचालित और यंत्रिकृत करके उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है।